



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 13, 2000/JYAIESTHA 23, 1922

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 2000/JYAISTHA 23, 1922

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2000

विषय: ऐसे देशों जिनमें ऐसे नियंत्रित वस्त्र व क्लाइंटिंग संबंधी उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अंतर्गत शामिल हैं के संबंध में परिधान और निटवियर नियंत्रित हकदारी^१ कोटा^२ नीति १२०००-२००४^३

सं. 1/68/2000-नियंत्रित I.— उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं ० १/१२८/१९९९-नियंत्रित-१ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, बाद में दिनांक १०-१२-१९९९ और ७-२-२००० की समसंब्यक्त अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था। इस अधिसूचना में निम्नानुसार और संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

२० पैरा ५॥३॥ के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए गए "प्रत्येक देश-श्रेणी में आवेदकों द्वारा आधार वर्ष के दौरान किए गये नियंत्रित के आधार पर परवर्ती वर्ष के ३१ अगस्त तक नियंत्रित के वसूल किये गये मूल्य पर समानुपात उपलब्ध स्तर आर्बोटेट किये जाएंगे। इनमें उपर्युक्त तारीख तक आधार वर्ष से पूर्व वर्षों से पूर्व वर्ष में किये गये नियंत्रित के वसूल किये गये मूल्य भी शामिल हैं। लेकिन, इसमें वह मूल्य शामिल नहीं होगा, जिसके लिए हकदारी विगत वर्षों में पहले से ही प्राप्त की गयी है। नियंत्रित का वसूल किया गया मूल्य के साथ इस उद्देश्य के लिए नियंत्रित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाय तथापि आवंटन आधार वर्ष के दौरान देश-श्रेणी में भारत के औसत वार्षिक नियंत्रित निष्पादन तक सीमित होंगे"।

३० पैरा-५ के उप-पैरा १०॥ के बाद उप-पैरा ११॥ शामिल किया जाएगा जो निम्नानुसार है :-

"अंतर्ण में उस तीसरे पक्ष के लेनदेन/वार्ताओं को भी शामिल किया जाएगा जिसमें हकदारी के धारक से अन्यत्र खाते में नियंत्रित आय जमा की जाएगी तथापि, अंतर्ण अवधि के दौरान स्वीकृत ऐसे तीसरे पक्ष के लेनदेन वार्ताओं के मामले में वसूल की गयी नियंत्रित आय हकदारी धारक द्वारा वसूल की गयी मानी जाएगी"।

इसके फलस्वरूप इसके पहले के उप-पैरा 11 और 12 बदलकर की क्रम संस्था बदलकर क्रमशः उप-पैरा 12 और 13 हो जाएगी ।

4. पैरा 7(4) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा :

" इस प्रणाली के अंतर्गत डकदारियों का परिकलन और आवंटन कोटा संचालन प्राधिकारी द्वारा आधार वर्ष के दौरान किये गये नियंत्रित के आधार पर परवर्ती वर्ष को 31 अगस्त तक स्वीकार्य नियंत्रित के वसूल किये गये मूल्य के आधार पर किये जाएंगे । इनमें ऐसे आधार वर्ष के पूर्व वर्षों में किये गये नियंत्रित मूल्य भी शामिल होंगे जिन्हें उपयुक्त तारीख तक वसूल किया गया है तोकिन द्वे मूल्य शामिल नहीं होंगे जिसके लिए विगत वर्षों में डकदारियां पहले से ही प्राप्त की गयी हैं नियंत्रित के वसूल किये गये मूल्य के साथ इस परियोजन के लिए नियंत्रित एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा । इस आवंटन नीति के अंतर्गत शामिल गैर-कोटा देशों को कोटा परियानों के नियंत्रितों को डकदारियों के निर्धारण के प्रयोजन से दोहरा महत्व दिया जाएगा । विशेषज्ञ आवेदकों को नियंत्रित के मूल्य के आधार पर उपलब्ध स्तर समानुपात वितरित किए जाएंगे ।

5. निम्नलिखित को उप-पैरा 17(3)(6) के बाद जोड़ा जाएगा ।

६३०. "कोटाओं के अंतर्ण की अनुमति नहीं है"

6. उप-पैरा 17(5) के बाद निम्नलिखित स्थापित किया जाए :-

" जिन ग्रामों में समिति नियंत्रितों को ऐसी धोखाधड़ी अथवा अन्य अनियमितताओं का दोषी पाती है, जो कि किसी भी उपयुक्त उपबंध का उल्लंघन होती है, उनके सम्बन्धित की जांच करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद नियंत्रित को निम्नलिखित में एक अपना अनेक दंड दिये जा सकते हैं:- [क] ईमांडी/बीजी राशि को जब्त करना; [ख] कोटा को जब्त करना तथा [ग] विशेषज्ञ अवधि के लिए डकदारियां प्राप्त करने तथा नियंत्रित डकदारी स्थितरण प्रणाली में भाग लेने से बहिष्कृत करना ।

7. उप-पैरा 17(10) के बाद निम्नलिखित उप-पैराओं को जोड़ा जाए:-

" 11. प्रवर्तन समिति सामन्यतया 6 मास की अवधि के भीतर सभी अपीलों का निपटन करेगी ।

" 12. प्रवर्तन अपील समिति सामन्यतः 6 मास की अवधि के भीतर सभी अपीलों का निपटन करेगी ।

8. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

MINISTRY OF TEXTILES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2000

Subject: Garment and Knitwear Export Entitlement (Quota) Policy (2000-2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.

No.1/68/2000-Exports-I, - 1. Attention is invited to Notification No.1/128/99Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notifications of even number dated 10th December, 1999 and 7th February, 2000 on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows.

2. Para 5(iii) shall be substituted by the following:-

“Available levels will be allotted pro-rata on the realised value of exports till 31st August of the succeeding year against the exports made during the base year by the applicants in each country-category. These will also include the value of exports made in the years prior to the base year realised till the above date, but would exclude the value for which the entitlement has already been obtained in previous years. Realised value of exports shall be supported by an affidavit prescribed for this purpose. Allotments, however, will be restricted to the average annual export performance of India in the country-category during the base year.”

3. Sub para (xi) after sub para (x) of para 5 is introduced as follows:-

“The term transfer shall also include the third party transactions/negotiations in which the export proceeds are credited to an account other than that of entitlement holder. However, export proceeds realised in case of such third party

transactions/negotiations during the period transfers are allowed, shall be deemed to be realised by the entitlement holder.”

Consequently, the earlier sub para (xi) and (xii) will be renumbered as sub para (xii) and (xiii) respectively.

4. Para 7(iv) shall be substituted by the following:-

“Entitlements under this system will be calculated and allotted by the Quota Administering Authority on the basis of realised value of admissible exports till 31st August of the succeeding year against the exports made during the base year. These will also include the value of exports made in the years prior to the base year realised till the above date, but would exclude the value for which the entitlement has already been obtained in previous years. Realised value of exports shall be supported by an affidavit prescribed for this purpose. The exports of quota garments, which are covered under this Allotment Policy, to non-quota countries will, however, be given double weightage for the purpose of determining entitlements. The levels available will be distributed pro-rata on the basis of the value of exports of individual applicants.”

5. The following may be added after Sub-para 17(iii)(d):-

“(e) Transfer of quotas which are not allowed”

6. Sub-para 17(v) may be substituted by the following:-

“In cases where the Committee finds the exporters guilty of fraud or other

irregularities, which are violative of any of the above provisions, after examining his explanation and giving a personal hearing, the exporter may be given one or many of the penalties by way of: (a) forfeiture of EMD/BG amount; (b) confiscation of quota; and (c) debarment from obtaining entitlements and participating in the Export Entitlement Distribution Scheme for a specified period."

7. After Sub-para 17(x), the following Sub-paras may be added:-

"(xi) The Enforcement Committee shall normally dispose of all appeals within a period of six months.

(xii) The Enforcement Appellate Committee shall normally dispose of all appeals within a period of three months."

8. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

